मध्यप्रदेश शासन

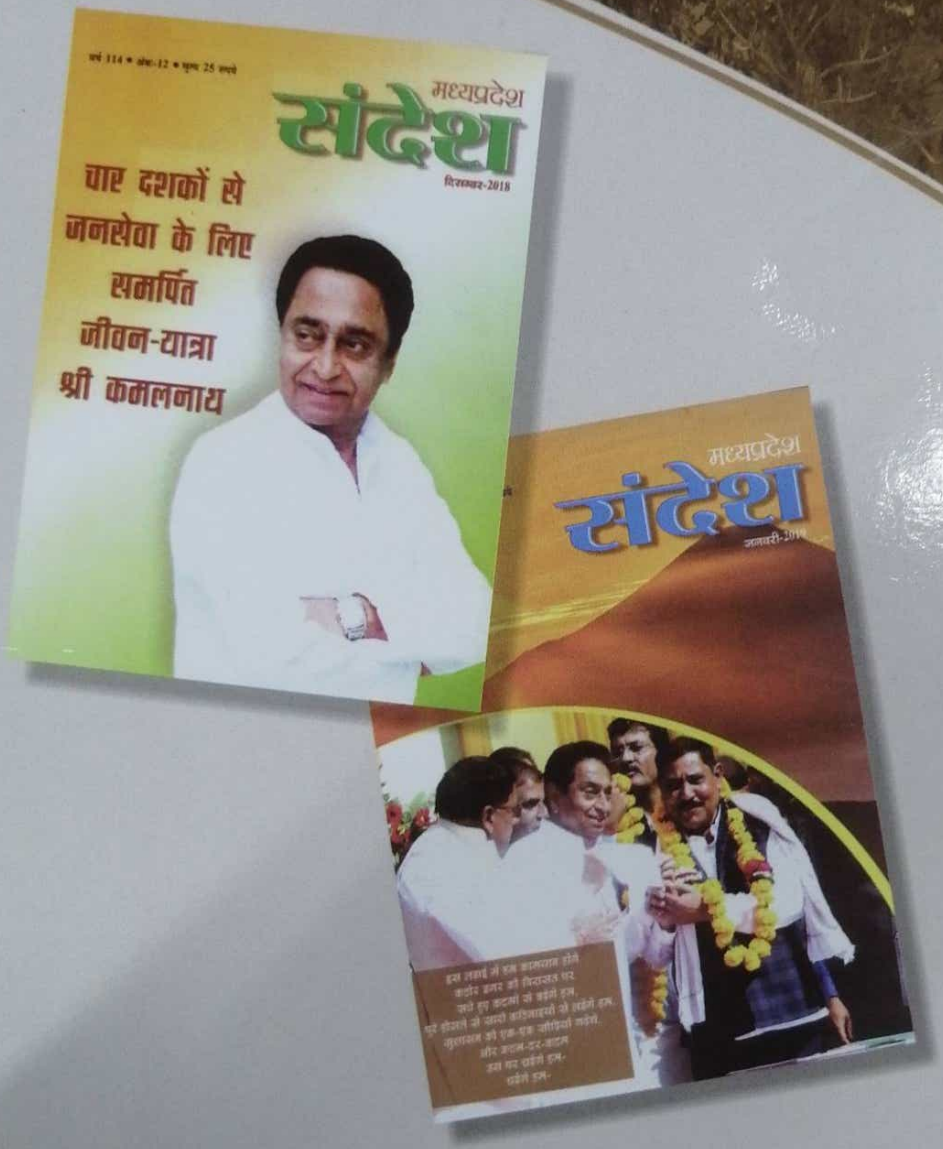

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2018-2019

जनसम्पर्क विभाग

www.mpinfo.org/www.mpnewsarch.org,
www.dprftp.com & District News Portal : www.dprmp.org

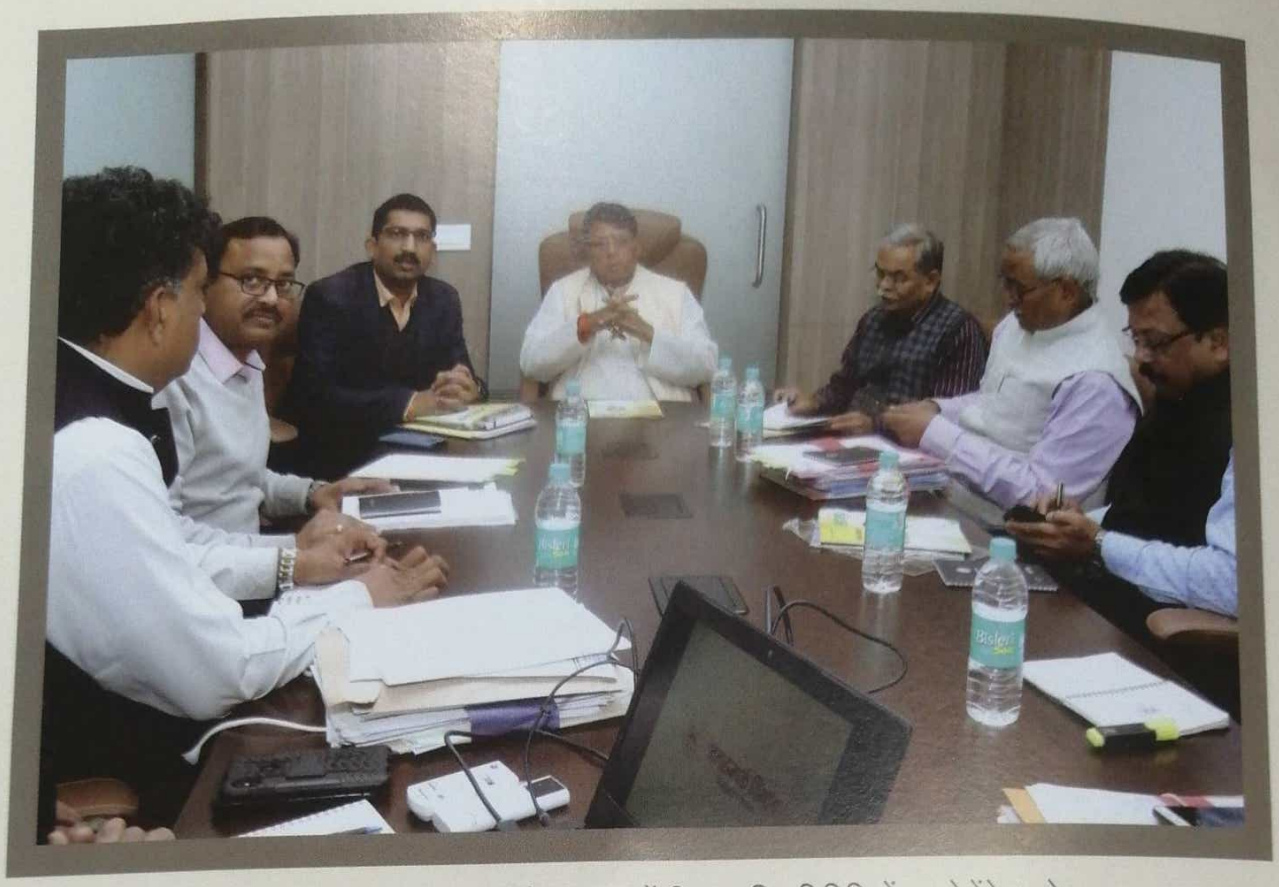

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने मंत्रालय में विभाग की गतिविधियों पर प्रेजेंटेशन देखा।
आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने मंत्रालय में राज्य शासन के मुखपत्र
''मध्यप्रदेश संदेश'' के नये अंक का लोकार्पण किया।

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2018-19

मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग

जनसम्पर्क विभाग

विभागीय मंत्री

पी.सी. शर्मा

अपर मुख्य सचिव

एम. गोपाल रेड्डी

सचिव/आयुक्त

पी. नरहरि

अपर सचिव

डॉ. एच.एल. चौधरी

विभागीय संरचना

कार्यालय

संचालनालय मुख्यालय	01	भोपाल
संभागीय कार्यालय	07	इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा
जिला कार्यालय	44	
राज्य के बाहर स्थापित कार्यालय	02	1. म.प्र. सूचना केन्द्र, नई दिल्ली 2. म.प्र. सूचना केन्द्र, मुम्बई
विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपक्रम/संस्था	02	1. मध्यप्रदेश माध्यम 2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

स्वीकृत पद

प्रथम श्रेणी	–	**53**	
द्वितीय श्रेणी	–	**78**	
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	–	**248**	**(20 सांख्येत्तर पदों सहित)**
तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	–	**232**	
चतुर्थ श्रेणी	–	**251**	
कुल	–	**862**	

विभागीय दायित्व

जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी प्रचार-प्रसार माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना और जन-मानस में शासन की उज्ज्वल छवि प्रस्तुत करना है। विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

समाचार प्रभाग

इस प्रभाग द्वारा शासन की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों/योजनाओं/नीतियों और उनकी उपलब्धियों के समाचार, विशेष लेख, सफलता की कहानियाँ, फोटो कव्हरेज, वीडियो कव्हरेज आदि करवाए जाते हैं। इन्हें समाचार-पत्रों को प्रकाशन तथा दूरदर्शन तथा अन्य निजी चैनलों को प्रसारण के लिये प्रतिदिन भेजा जाता है। साथ ही मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के प्रवक्ता के रूप में उनसे संबद्ध जनसम्पर्क अधिकारी उनका मीडिया संबंधी काम करते हैं।

वर्ष 2018 में दिसम्बर माह तक हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में कुल 7430 समाचार जारी किये गये। साथ ही 53 विशेष लेख/संदर्भ हिन्दी में विभिन्न समाचार-पत्र/पत्रिका को प्रकाशन के लिये जारी किये गये।

समाचार, विशेष लेख, संदर्भ और सफलता की कहानियाँ उर्दू और संस्कृत भाषा में अनुवाद कराकर वेबसाइट पर अपलोड की गईं। उर्दू समाचार, लेख आदि उर्दूभाषी समाचार-पत्रों को वितरित किये गये।

इसी प्रकार संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा इस अवधि में लगभग 1 लाख 34 हजार 065 समाचार स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिये भेजे गये।

मा. मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों, अन्य विभाग प्रमुखों के लिये प्रेस ब्रीफिंग और पत्रकार-वार्ताओं का आयोजन भी आलोच्य अवधि में समय-समय पर किया गया।

प्रभाग द्वारा इसी अवधि में वर्ष 2018 के बजट सत्र के लिये राज्यपाल का अभिभाषण, 15 अगस्त के लिये मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संदेश, 26 जनवरी 2018 के लिये राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संदेश तैयार किया गया। साथ ही विभागीय वेबसाइट की जानकारियों को समय-समय पर अद्यतन किया गया। स्वाधीनता दिवस, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस-2019 के कव्हरेज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रमों के लिये समाचार-पत्र प्रतिनिधियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रवेश-पत्रों का वितरण किया गया। सभी शासकीय आयोजनों के आमंत्रण-पत्र शाखा द्वारा मीडिया को वितरित किये गये। विशेष अवसरों पर समाचार-पत्रों में विशेष लेखों का प्रकाशन करवाया गया।

समाचार में विविधता और नयापन लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस क्रम में प्राचीन धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थलों की जानकारी, साम्प्रदायिक सद्भाव, आसपास की घटनाओं, खेलों तथा योजनाओं पर आधारित समाचारों के अलावा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता पर आधारित समाचार भी प्रतिदिन ज्यादा संख्या में जारी किये जा रहे हैं।

विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ताएँ और प्रेस ब्रीफिंग के आयोजन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी समाचार जारी किये गये। निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना हेतु मीडियाकर्मियों को प्राधिकार-पत्र जारी किये गये।

आलोच्य अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयोगों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का भी शाखा द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।

संचार प्रभाग

प्रतिवेदित अवधि में विभाग की संचार प्रणाली को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ किया गया। प्रचार-प्रसार तथा समाचारों/सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान में सुविधा की दृष्टि से 28 कम्प्यूटर, 14 लेपटाप, स्केनर A3- 51 और 33 आल-इन-वन प्रिन्टर को बदला गया।

इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों पर राष्ट्रीय/प्रादेशिक और स्थानीय स्तर के प्रसारित बुलेटिनों के दृष्टिगत विभिन्न घटनाक्रमों/गतिविधियों संबंधी न्यूज की सतत् मॉनीटरिंग और रिकार्डिंग के लिये मुख्यालय में स्थापित मॉनीटरिंग सेल में 20 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय चैनलों के न्यूज बुलेटिनों और प्रदेश पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की गई। दिनभर की खबरों का प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री और विभिन्न स्तरों पर भेजा गया।

वेबसाइट

विभाग की मुख्य वेबसाइट www.mpinfo.org को नवीनतम टेक्नोलॉजी के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाकर मोबाइल, टेबलेट और अन्य डिवाइस आधारित बनाया गया। इस साइट पर हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत सहित चार भाषाओं में समाचार/लेख आदि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जारी किये जाने वाले समाचार, जन-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लेख, सफलता की कहानी, माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विजुअल्स, मंत्रि-परिषद् के निर्णय, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण, शासकीय विभागों की नीतियाँ, फ्लेगशिप योजनाएँ, शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण अभियान, कृषि महोत्सव, पुरस्कार, सम्मान और सराहना, विशेष अभियान, कला एवं संस्कृति, विकास गतिविधियाँ, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की जानकारी, विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, विज्ञापन, अधिमान्यता, पत्रकार दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा, पत्रकार पुरस्कार योजना, मीडिया प्रतिनिधि कल्याण सहायता संबंधी नियम, अचल सम्पत्ति के विवरण, नवीन सूचनाएँ, लोक सूचना एवं अपीलीय अधिकारी, विज्ञापनों के रिलीज ऑर्डर और सम-सामयिक संदर्भ के साथ ही मंत्रि-परिषद्, प्रशासनिक अधिकारियों की सूची तथा विभिन्न विभागों के ई-मेल और पते उपलब्ध हैं।

साइट पर सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्वीटर एवं यू-ट्यूब) पर विभागीय गतिविधियाँ भी प्रदर्शित हैं। अब यह साइट पहले से बेहतर और यूजर फ्रेन्डली हो गई है। साइट को प्रतिवेदित अवधि में 22 करोड़ 56 लाख 47 हजार 807 हिट्स प्राप्त हुए।

जिलों के समाचारों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmp.org कार्यरत है। पोर्टल पर जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि में 1 लाख 29 हजार 164 समाचार अपलोड किये गये। इस पोर्टल को प्रतिवेदित अवधि में 06 करोड़ 04 लाख 01 हजार 584 हिट्स प्राप्त हुए। राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं की क्लीपिंग देखने के लिये कार्यरत विभागीय वेबसाइट www.mpnewsarch.org को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाकर यूजर्स फ्रेन्डली बनाया गया। इस साइट को भी 46 लाख 45 हजार 084 हिट्स मिले।

फोटो - फिल्म प्रभाग

प्रभाग द्वारा मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण के अतिरिक्त अन्य सभी शासकीय कार्यक्रमों/ आयोजनों/ बैठकों के वीडियो/फोटो कव्हरेज तथा आवश्यकतानुसार छायाचित्रों के एलबम तैयार करवाये जाते हैं।

विभाग द्वारा मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण एवं सभी शासकीय कार्यक्रमों/आयोजनों के वीडियो कव्हरेज करवाकर प्रतिदिन दूरदर्शन एवं अन्य स्थानीय टी.व्ही. चैनल को प्रसारण के लिये विभागीय वेबसाइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये जाते हैं। इस दौरान 1418 वीडियो कव्हरेज एफ.टी.पी. के जरिये प्रसारण के लिये भेजे गये।

प्रतिवेदित अवधि में शासकीय कार्यक्रमों के फोटो कव्हरेज के छाया-चित्र वेबसाइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये गये। संभागीय एवं जिला कार्यालयों के भी छायाचित्रों को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजा गया। इस अवधि में मुख्यालय द्वारा 1620 फोटो कव्हरेज करवाये गये।

मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं, जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सफलता की कहानियों के आधार पर एक-एक मिनिट के 25 न्यूज कैप्सूल्स का निर्माण करवाकर इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों पर प्रसारित करवाया गया।

फिल्म-निर्माण प्रभाग

फिल्म निर्माण प्रभाग द्वारा प्रतिवेदित अवधि में मध्यप्रदेश शासन की जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों/ निर्णयों और उनकी उपलब्धियों पर केन्द्रित तथा पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के विषयों पर केन्द्रित 78 वीडियो स्पॉट निर्मित करवाये गये।

सोशल मीडिया

वर्तमान में सोशल मीडिया सम्प्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। विशेष तौर पर युवा वर्ग तक अपनी बात पहुँचाने का सबसे प्रमुख जरिया सोशल मीडिया और मोबाइल जर्नलिज्म (मोजो) है। इसके महत्व को समझते हुए विभाग ने प्रदेश स्तर की सोशल मीडिया विंग का गठन किया। सोशल मीडिया विंग रीयल टाइम में शासकीय समाचारों को लोगों तक पहुँचाने का अब सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

सोशल मीडिया विंग द्वारा सीएमओ, जनसम्पर्क एमपी के एकाउंट के साथ साथ प्रदेश के 45 शासकीय विभागों के फेसबुक और ट्वीटर एकाउंट संचालित किये जा रहे हैं। यह सभी एकाउंट वेरीफाई कराये गये हैं। इनका संचालन भोपाल की सोशल मीडिया टीम द्वारा किया जाता है।

विभागीय अधिकारी इस नई विधा में बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसके लिए एक बार राज्य स्तरीय एवं दो बार संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक जिला जनसम्पर्क कार्यालय में एक-एक सोशल मीडिया हैंडलर भी अंशकालिक तौर पर दिये गये हैं।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा 334 सोशल मीडिया एकाउंट्स चलाये जा रहे हैं। इनमें CMO का फेसबुक और ट्वीटर एकाउंट, जनसम्पर्क विभाग का फेसबुक और ट्वीटर एकाउंट, 44 विभागों के सोशल मीडिया (फेसबुक व ट्वीटर) एकाउंट्स, 10 संभागायुक्तों के सोशल मीडिया (फेसबुक व ट्वीटर) एकाउंट्स, 51 जिलों के कलेक्टर के सोशल मीडिया (फेसबुक व ट्वीटर) एकाउंट्स, 10 संभागों के सयुंक्त संचालक जनसम्पर्क के सोशल मीडिया (फेसबुक व ट्वीटर) एकाउंट्स, 51 जिलों के PRO के सोशल मीडिया (फेसबुक व ट्वीटर) एकाउंट्स शामिल हैं। विभाग द्वारा संचालित सभी फेसबुक पेज पर 15 लाख से अधिक लाइक्स और ट्वीटर पर 12 लाख से अधिक फॉलोवर उपलब्ध हैं।

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के सभी महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों को लाइव किया जाता है। सीएमओ के एकाउंट पर मुख्यमंत्री की गतिविधियों को रीयल टाइम अपडेट किया जाता है। मुख्यमंत्री के संदेश आकर्षक ग्राफिक्स के जरिए त्वरित रूप से ट्वीट व पोस्ट किये जाते हैं।

सोशल मीडिया पर सप्ताह में पाँच दिन 'जनसम्पर्क ख़बरें' और 'दस संभाग- दस ख़बरें' नाम से बुलेटिन जारी कर शासन की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराने की नई पहल इस अवधि में की गई। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों पर हितग्राहियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित वीडियो सेग्मेंट 'मुस्कान का आधार-प्रदेश सरकार' और 'खुशियों की दास्तां' सोशल मीडिया एकाउंट्स पर पोस्ट की जा रही हैं।

विभाग का सक्रिय यूट्यूब चैनल है, जिस पर 30 हजार से अधिक सब्स्क्राइबर हैं। इसमें 51 जिले के अलग-अलग वीडियो सेगमेंट हैं। जनसम्पर्क विभाग का Linkedin पेज बनाया गया है। इसके माध्यम से वर्किंग प्रोफेशनल्स तक उनके इन्ट्रेस्ट का शासन का सन्देश पहुँचाया जा रहा है। विभाग का Instagram - Account बनाया गया है, जिसके माध्यम से युवा तबके तक शासन-प्रशासन की गतिविधियों को तस्वीरों एवं आकर्षक ग्राफिक्स के ज़रिये पहुँचाया जा रहा है।

विभाग द्वारा युवाओं के लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार-पत्र 'रोजगार और निर्माण' का ई-पेपर एडीशन भी प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन का मासिक मुखपत्र 'मध्यप्रदेश संदेश' भी इस अवधि में पहली बार ई-मैगजीन के रूप में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया। विभाग द्वारा प्रतिदिन के समाचारों पर आधारित 'जनसम्पर्क टुडे' नाम से ई-न्यूज लेटर जारी करना प्रारंभ किया गया।

संदर्भ प्रभाग

संचालनालय के संदर्भ प्रभाग में विभिन्न विषय की पुस्तकें संकलित हैं। ये पुस्तकें समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन, पठन-पाठन तथा संदर्भ के उपयोग में आती हैं। इसके अलावा भोपाल में न्यू मार्केट स्थित जीटीबी कॉम्प्लेक्स में एक सूचना केन्द्र संचालित है। यह सूचना केन्द्र प्रतिदिन दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आमजन के लिये खुला रहता है। पाठकों के पढ़ने के लिये समाचार-पत्रों के अलावा विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती हैं। गत वर्ष लगभग 9,500 पाठकों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया।

वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संदर्भ प्रभाग की लायब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इसी क्रम में लायब्रेरी की लगभग 20 हजार पुस्तकों की पृविष्टियाँ अभी तक की जा चुकी हैं। शेष कार्य भी प्रगति पर है।

विज्ञापन प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी विभाग/कार्यालय की निर्माण/निविदा/भर्ती सूचनाओं का समाचार-पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशन करवाने का कार्य किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रदर्शन विज्ञापन के माध्यम से प्रिंट मीडिया एवं न्यूज कैप्सूल/वीडियो स्पॉट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार करवाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी प्रभाग द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2018 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दूरदर्शन/आकाशवाणी, 'विविध भारती', टी.वी. न्यूज चैनलों, प्राइवेट रेडियो एफ.एम. चैनलों, कम्युनिटी रेडियो, वेबसाइट/वेबपोर्टल, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं/विकासात्मक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार कराया गया। साथ ही विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के लिए निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। विशेषत: ईव्हीएम व्हीव्हीपेट, आइये जानें कैसे बनाएं मतदाता परिचय-पत्र, दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीयन एवं अन्य मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक वीडियो स्पॉट का प्रसारण कराया गया।

पारदर्शिता और सुगमता की दृष्टि से वर्गीकृत तथा प्रदर्शन विज्ञापन सामग्री और विज्ञापन आदेश ऑनलाइन जारी किये जाते हैं। इस अवधि में विज्ञापन देयकों का शत-प्रतिशत भुगतान ई-पेमेंट से किया गया।

प्रभाग द्वारा विज्ञापन देयकों के ऑनलाइन भुगतान के साथ ही विज्ञापन आदेश एवं विज्ञापन सामग्री भी ऑनलाइन दी जा रही है। इसको और अधिक उन्नत करते हुए विभिन्न विभागों से विज्ञापन सामग्री एवं प्रचार-प्रसार विज्ञापनों के देयक ऑनलाइन बुलाने के लिये कम्प्यूटर प्रणाली को और अधिक विकसित किया जा रहा है।

कैलेंडर वर्ष 2018 में कुल 16 हजार 254 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें 13 हजार 960 वर्गीकृत और 2294 प्रदर्शन विज्ञापन शामिल हैं।

प्रकाशन प्रभाग

जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का आईना होते हैं। प्रदेश की लोकहितकारी नीतियों, योजनाओं और प्रदेश के जीवन तथा समाज के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित प्रकाशनों के लेखन, सम्पादन और मुद्रण का कार्य संचालनालय की प्रकाशन शाखा द्वारा किया जाता है। इन प्रकाशनों में किताबें, लघु-पुस्तिकाएँ, फोल्डर, पैम्फलेट्स, पोस्टर तथा मासिक पत्रिका 'मध्यप्रदेश संदेश' शामिल हैं।

मध्यप्रदेश संदेश

प्रदेश सरकार की आमुख पत्रिका 'मध्यप्रदेश संदेश' हर माह प्रकाशित होने वाली नियमित पत्रिका है। संदेश का प्रत्येक अंक एक समयानुकूल आवरण कथा पर केन्द्रित किया जा रहा है। पत्रिका में मुख्यत: प्रदेश की जन-कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की जाती है। संदेश को नये कलेवर के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा इस पत्रिका में प्रदेश की विशिष्टताओं, विभिन्नताओं और विलक्षणताओं पर तथा जीवन और समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्व, तीज-त्यौहार, परम्पराओं, लोक जीवन, वन और वन्य- जीवन, पर्यटन, खेल, सिनेमा तथा साहित्यिक गतिविधियों और प्रदेश से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्वों एवं विकास की विभिन्न अवधारणाओं पर वरिष्ठ और युवा लेखकों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

लोकहित कार्यों पर प्रकाशन

मध्यप्रदेश सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यों की जानकारियाँ दूर-सुदूर गाँवों में रहने वाले लोगों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकाशन किए गए। इन प्रकाशन को जिला मुख्यालयों पर स्थित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से जन-सामान्य तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा ऐसे विशिष्ट आयोजनों में इन प्रकाशनों का वितरण किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में जन-समुदाय उपस्थित था।

प्रदेश सरकार ने जिन गरीबों, शोषितों, पिछड़ों तथा वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, उन्हें ऐसी योजनाओं की जानकारी देने और लाभ लेने के सुलभ तरीकों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाने वाली पुस्तिका 'आगे आयें -लाभ उठायें' का नया और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया गया है।

पत्र–परिनिरीक्षण प्रभाग

इस प्रभाग में मुख्य रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सांध्यकालीन समाचार–पत्रों की कतरनों के बंच तैयार कर शासन के प्रमुख स्तरों पर प्रेषित किया जाता है। प्रभाग द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 2018 की अवधि में लगभग 96 लाख 42 हजार 959 समाचार कतरनें विभिन्न स्तरों यथा मा. राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जनसंपर्क, माननीय समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, सभी प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित निर्देशानुसार अन्य स्तरों पर प्रेषित की गई।

प्रभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पृथक पत्र–परिनिरीक्षण यूनिट स्थापित कर निर्वाचन संबंधी समाचार कतरनों को शीघ्रता से उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया।

दिल्ली से आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय समाचार–पत्रों के ई–पेपर में प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण समाचारों के परिनिरीक्षण का कार्य भी प्रभाग के वेबसाइट कक्ष में संपादित किया गया।

उल्लेखित अवधि में प्रभाग द्वारा उच्च स्तरों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित संदर्भ कतरनों को तत्परता पूर्वक समय–सीमा में उपलब्ध कराने का कार्य भी संपादित किया गया।

पंजीयन प्रभाग

इस प्रभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से प्रकाशित हो रहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार–पत्रों के साथ ही मासिक, त्रैमासिक तथा अन्य नियतकालिक पत्र–पत्रिकाओं को एक वर्ष तक जिलेवार संधारित किया जाता है।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग द्वारा राज्य शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकासात्मक उपलब्धियों एवं कार्यक्रम को आमजन तक पहुँचाने के लिए आउटडोर ब्रांडिंग एवं आधुनिक जनसंचार के माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया गया।

विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप प्लान का प्रचार–प्रसार होर्डिंग्स, बैनर, दीवार लेखन, प्रचार रथ और ऑटो रिक्शा के पीछे मतदाता जागरूकता के संदेश का प्रचार किया गया।

अधिमान्यता प्रभाग

अधिमान्यता नियम के अनुसार पत्रकारों को राज्य/जिला एवं तहसील-स्तरीय अधिमान्यता दी जाती है। इसके लिये राज्य तथा संभागीय अधिमान्यता समितियाँ गठित हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार इन समितियों के सदस्य होते हैं।

राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के राज्य स्तरीय अधिमान्यता और संभागीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता संबंधी प्रकरणों में अनुशंसा करती है। वर्ष 2017 से अधिमान्यता कार्ड का नवीनीकरण/नवीन अधिमान्यता के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इन कार्ड की अवधि अब दो वर्ष कर दी गई है।

अधिमान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। प्रदेश में दिसंबर 2018 की स्थिति में 1157 राज्य, 1965 जिला एवं 812 तहसील स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं।

पत्रकारों को आर्थिक सहायता

पत्रकारों को स्वयं, उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को एवं परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है। उपचार के लिए पात्रता और आवश्यकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति गठित है। समिति द्वारा प्राप्त सहायता आवेदनों पर की गई अनुशंसा के अनुसार सहायता की कार्रवाई की जाती है। सामान्य बीमारियों के लिये 20 हज़ार रूपये तक एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम रूपये 50 हज़ार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उन पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि 4.00 लाख रूपये है।

अनुदान

वर्ष 2018-19 में माधवराव सप्रे समाचार-पत्र संग्रहालय, भोपाल को 10.00 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।

फैलोशिप

स्व. राजेन्द्र माथुर स्मृति पत्रकारिता फैलोशिप के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक पत्रकार को एक लाख रूपये की राशि देने का प्रावधान है।

पत्रकारिता सम्मान

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिये उत्साहजनक वातावरण बनाये जाने और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता सम्मान प्रारम्भ किये गये हैं। वर्ष 2016 तक के यह सम्मान वितरित किये जा चुके हैं । पत्रकारों को विशिष्ट योगदान के लिये सम्मानित करने के उद्देश्य से नीचे दर्शाये अनुसार सम्मान स्थापित किये गये हैं :–

राष्ट्रीय सम्मान (राशि 2.51 लाख रुपये)

1. गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)
2. राजेन्द्र माथुर राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)
3 विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)

राज्य स्तरीय सम्मान (राशि 1.51 लाख रुपये)

1. महेन्द्र चौधरी राज्य स्तरीय (फोटो) पत्रकारिता सम्मान (एक)
2. सत्यनारायण श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान (एक)

आंचलिक पत्रकारिता सम्मान (राशि 1.01 लाख रुपये)

1.	स्व. शरद जोशी सम्मान	भोपाल अंचल के पत्रकारों के लिये
2.	स्व. राहुल बारपुते सम्मान	इंदौर अंचल के पत्रकारों के लिये
3.	स्व. बनारसीदास चतुर्वेदी सम्मान	रीवा अंचल के पत्रकारों के लिये
4.	स्व. रतनलाल जोशी सम्मान	ग्वालियर अंचल के पत्रकारों के लिये
5.	स्व. जीवनलाल वर्मा विद्रोही सम्मान	जबलपुर अंचल के पत्रकारों के लिये
6.	स्व. कन्हैयालाल वैद्य सम्मान	उज्जैन अंचल के पत्रकारों के लिये
7.	स्व. मास्टर बलदेव प्रसाद सम्मान	सागर अंचल के पत्रकारों के लिये

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय टेलीविज़न पत्रकारिता सम्मान

राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकारों एवं कैमरामेन के सम्मान के लिये भी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.	राष्ट्रीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान	राशि 1.51 लाख रूपये (एक)
2.	राष्ट्रीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान	राशि 1.01 लाख रूपये (एक)
3.	राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान	राशि 1.51 लाख रूपये (एक)
4.	राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान	राशि 1.01 लाख रूपये (एक)

श्रद्धा–निधि

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग 159 पत्रकारों को रूपये 7 हज़ार प्रतिमाह श्रद्धानिधि प्रदान की जा रही है।

लेपटॉप

शासन ने राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटॉप देने की अभिनव योजना प्रारम्भ की है। इसके अर्न्तगत दिसम्बर 2018 की स्थिति में 848 राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटॉप क्रय करने के लिये राशि का भुगतान किया गया।

संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

शासन द्वारा मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की गई है। योजना में स्वास्थ्य बीमा 2.00 एवं 4.00 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5.00 लाख एवं 10.00 लाख रुपये का है। योजना में दिसम्बर 2018 तक लगभग 2258 संचार प्रतिनिधि का बीमा हो चुका है।

पत्रकार प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश के जिलों/तहसीलों में पत्रकारों के लिये मीडिया संवाद कार्यक्रम'' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यप्रदेश के जिलों में कार्यरत पत्रकारों को पत्रकारिता के कौशल की बारीकियों पर चर्चा कर उन्हें नवीन तकनीक, प्रेस एक्ट और संविधान में उल्लेखित प्रेस से जुड़े कानूनों से परिचित कराना है।

आवास ऋण ब्याज अनुदान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान 05 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

नवीन अभिनव कार्य–योजना

आर्थिक सहायता

- पत्रकारों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की परिभाषा में आश्रित माता–पिता को शामिल किया गया है।
- अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि बढ़ाकर 4.00 लाख रूपये की गई है।

श्रद्धा निधि

- प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि में आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है।
- वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि राशि रूपये 6 हज़ार से बढ़ाकर 7 हज़ार की गई है।

बीमा योजना

- संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में इस वर्ष से नियमित योजना राशि के साथ विकल्प स्वरूप 4.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10.00 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल किया गया है।

आवास ऋण ब्याज अनुदान

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपक्रम/संस्थाएँ

मध्यप्रदेश माध्यम

मध्यप्रदेश माध्यम की स्थापना जन-संचार के क्षेत्र में तेजी से होते बदलावों और नये समय में संचार की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग के सृजनात्मक उपक्रम के रूप में हुई है।

पिछले दो दशक से अधिक समय से मध्यप्रदेश माध्यम, राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये संचार की सभी विधाओं में कार्य कर रहा है। संस्था युवाओं के लिये साप्ताहिक रोजगार और निर्माण के प्रकाशन के साथ शासकीय विभागों के लिये विभिन्न प्रकाशन और फिल्मों का निर्माण भी करता है।

''रोजगार और निर्माण'' मध्यप्रदेश माध्यम से प्रकाशित होने वाला नियमित साप्ताहिक समाचार-पत्र है। इसकी लगभग 70 हजार प्रतियाँ प्रति सप्ताह प्रकाशित होती हैं। मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक यह पत्र पहुँचता है। प्रकाशन की नियमितता और गुणवत्ता के कारण पत्र की विशिष्ट पहचान बनी है।

संचार के इस समय में ग्रामीण संचार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मासिक पत्रिका 'मध्यप्रदेश पंचायिका' का प्रकाशन भी पिछले दो दशक से मध्यप्रदेश माध्यम कर रहा है।

वर्ष 2018 के शासकीय कैलेण्डर का विशेष स्वरूप में आकल्पन किया गया। संस्था द्वारा विशेष मीडिया कैम्पेन्स, जिसमें विभिन्न योजनाओं का इवेंट मैनेजमेंट, का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया।

संस्था के वर्ष 2017-2018 तक के अंतिम लेखा तैयार कर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स द्वारा अंकेक्षण किया जा चुका है। संस्था के वर्ष 2016-2017 तक के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर द्वारा किया जा चुका है।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 28 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ कुशल मीडियाकर्मियों के निर्माण के ढाई दशक से अधिक की यात्रा में विश्वविद्यालय से निकले हजारों विद्यार्थी मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ अपना व्यावसायिक योगदान दे रहे हैं। विगत् शैक्षणिक सत्र में अकादमिक कार्यकलापों के साथ अनेक आयोजनों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्णिम यात्रा को डिजिटल युग के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प जारी रखा है।

27 वर्षों की यात्रा में हिन्दी पत्रकारिता पर विशेष फोकस के साथ विश्वविद्यालय पत्रकारिता, जनसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण–प्रशिक्षण, शोध और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है। तेजी से विस्तृत हो रहे मीडिया के समग्र क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित पत्रकार और मीडिया व्यवसायी उपलब्ध कराना, हिन्दी और अन्य भाषाई पत्रकारिता के बीच अंतर–संवाद, मीडिया के सामाजिक सरोकारों पर विमर्श एवं मीडिया एवं संचार के विविध आयाम पर उत्कृष्ट शोध गतिविधियों का संचालन विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है।

मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रतिष्ठित केंद्र

मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पाँच अन्य परिसर क्रमश: नोएडा, खण्डवा, ग्वालियर, रीवा, अमरकंटक में संचालित हैं। विश्वविद्यालय में मीडिया शिक्षा, मीडिया प्रबंधन, जनसंपर्क, नवीन मीडिया, प्रिंटिंग पैकेजिंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध विभिन्न विषयों/संकायों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पी.एचडी. जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

वर्तमान में संचार संबंधित पेशेवर पाठ्यक्रमों की मांग के अनुरूप वीडियो प्रोडक्शन, वेब संचार, फिल्म पत्रकारिता, डिजिटल फोटोग्राफी, भारतीय संचार परंपराएँ, पर्यावरण संचार, इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एवं यौगिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं आध्यात्मिक संचार में अंशकालिक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी भोपाल परिसर में संचालित हैं।

विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग एवं पाँच अध्ययन परिसर में शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2018 से जून 2019) में कुल 954 विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 28 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ कुशल मीडियाकर्मियों के निर्माण के ढाई दशक से अधिक की यात्रा में विश्वविद्यालय से निकले हजारों विद्यार्थी मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ अपना व्यावसायिक योगदान दे रहे हैं। विगत् शैक्षणिक सत्र में अकादमिक कार्यकलापों के साथ अनेक आयोजनों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्णिम यात्रा को डिजिटल युग के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प जारी रखा है।

27 वर्षों की यात्रा में हिन्दी पत्रकारिता पर विशेष फोकस के साथ विश्वविद्यालय पत्रकारिता, जनसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण-प्रशिक्षण, शोध और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है। तेजी से विस्तृत हो रहे मीडिया के समग्र क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित पत्रकार और मीडिया व्यवसायी उपलब्ध कराना, हिन्दी और अन्य भाषाई पत्रकारिता के बीच अंतर-संवाद, मीडिया के सामाजिक सरोकारों पर विमर्श एवं मीडिया एवं संचार के विविध आयाम पर उत्कृष्ट शोध गतिविधियों का संचालन विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है।

मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रतिष्ठित केंद्र

मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पाँच अन्य परिसर क्रमश: नोएडा, खण्डवा, ग्वालियर, रीवा, अमरकंटक में संचालित हैं। विश्वविद्यालय में मीडिया शिक्षा, मीडिया प्रबंधन, जनसंपर्क, नवीन मीडिया, प्रिंटिंग पैकेजिंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध विभिन्न विषयों/संकायों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पी.एचडी. जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

वर्तमान में संचार संबंधित पेशेवर पाठ्यक्रमों की मांग के अनुरूप वीडियो प्रोडक्शन, वेब संचार, फिल्म पत्रकारिता, डिजिटल फोटोग्राफी, भारतीय संचार परंपराएँ, पर्यावरण संचार, इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एवं यौगिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं आध्यात्मिक संचार में अंशकालिक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी भोपाल परिसर में संचालित हैं।

विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग एवं पाँच अध्ययन परिसर में शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2018 से जून 2019) में कुल 954 विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

देशभर में विश्वविद्यालय के 67 मीडिया व 1772 कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की कुल 1839 सहयोगी अध्ययन संस्थाएँ हैं। इनके माध्यम से देशभर के सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थी भी मीडिया और कम्प्यूटर के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की सहयोगी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2018 से जून 2019) में कुल 81 हजार 29 विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

दूसरे वर्ष में च्वाइस्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) सफलता से संचालित

वर्ष 2017 में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(CBCS) एवं राष्ट्रीय आकलन एवं मान्यता परिषद (NAAC) की अनुशंसाओं के अनुसरण में रेग्यूलेशन 25(धारा-51)का गठन करते हुए च्वाइस्ड बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) प्रणाली सफलता से लागू की गई। इसके अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के सभी विद्यार्थियों को अपनी स्वेच्छा से एक प्रश्न-पत्र किसी भी स्ट्रीम से चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। प्रणाली की विशेषता यह है कि मीडिया पाठ्यक्रम करने वाला विद्यार्थी भी यदि चाहे तो कम्प्यूटर विषय का एक प्रश्न-पत्र ऐच्छिक विषय (Open Election) के रूप में चुन सकता है और कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का विद्यार्थी भी मीडिया संबंधी विषय का एक प्रश्न-पत्र ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकता है।

मान्यता

यू.जी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय को जनवरी 2018 से 12वीं की मान्यता प्रदान की गई। इस शैक्षणिक सत्र में कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं मीडिया प्रबंधन विभाग के पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) से प्राप्त मान्यता का नवीनीकरण हुआ।

मध्यप्रदेश में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का सफलता से संचालन

वर्ष 2016 में डीसीए (DCA) पाठ्यक्रम की कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित करने की दिशा में कदम उठाया गया था। जून 2018 में डीसीए (DCA) पाठ्यक्रम की तृतीय ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा सफलता से आयोजित की गई। इसके तहत डीसीए प्रथम सेमेस्टर के 36 हजार 921 छात्र एवं द्वितीय सेमेस्टर के 39 हजार 936 छात्रों की ऑनलाईन परीक्षा देशभर में स्थित 162 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई। अगले चरण में जनवरी 2019 में डीसीए प्रथम एवं द्वितीय, दोनों सत्रों के लिए कुल 160 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें कुल 76 हजार 823 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

कैशलेस एकोनॉमी

विश्वविद्यालय विगत सात वर्षों से प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, माइग्रेशन, डिग्री-डिप्लोमा, डुप्लीकेट अंकसूची आदि समस्त शुल्क ऑनलाइन प्रणाली से ही प्राप्त कर रहा है।

प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट प्रकोष्ठ विभिन्न विभाग के विद्यार्थियों को प्लेसमेंट पूर्व इंटर्नशिप उपलब्ध कराने तथा अंतिम प्लेसमेंट हेतु सतत् प्रयासरत रहता है। प्रकोष्ठ विगत वर्षों से कैम्पस प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविर में विद्यार्थियों को चयनित कर नौकरी देने वाले संस्थानों में एबीपी न्यूज, ईटीवी भारत,बिजनेस स्टेंडर्ड, टाईम्स ऑफ इंडिया, सी वोटर, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नेटवर्क 18, भास्कर न्यूज, बालाजी फिल्म्स, सोनी फिल्म्स, बीबीसी, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाईम्स, दैनिक हिन्दुस्तान, एनडीटीवी, दैनिक जागरण, आईएनएच, बंसल न्यूज, पंजाब केसरी आदि प्रमुख हैं।

विश्वविद्यालय के प्रकाशन

(क) प्रकाशित पुस्तकें – **लेखक/संपादक**

1. रतौना आंदोलन–हिन्दू–मुस्लिम एकता का सेतुबंध – बृजेन्द्र शरण श्रीवास्तव
2. Untold Story of Maharaja Hari singh : Jammu Kashmir (1915-40) – Devesh Khandelwal

(ख) प्रकाशनाधीन पुस्तकें

1. कबीर वाणी में संचार पद्धति एवं परम्परा – साकेत दुबे
2. समाज विज्ञापन, संचार एवं प्रबंधन में अनुसंधान कौशल विकास – डॉ. बी.एस. नागी, डॉ. ए.एम. खान
3. जनसपंर्क एवं निगमित संचार – डॉ. नीमोधर
4. एक अनकही कहानी हरीसिंह : जम्मू कश्मीर के महाराज – देवेश खंडेलवाल
5. Communication concept and process Swami Vivekananda – Girish Upadhyay
6. Secularism in English Dailies – Devesh Khandelwal

(ग) प्रकाशनाधीन प्रतिवेदन

1. महाकुंभ 2013- आम भारतीय के संवाद और विचार का संसार।
2. चुनाव परिप्रेक्ष्य में लोक-विमर्श की प्रक्रिया का अध्ययन।

(घ) नियमित प्रकाशन

1. **मीडिया मीमांसा** - त्रैमासिक शोध पत्रिका (जर्नल)।
2. **मीडिया नवचिंतन** - जनसंचार एवं मीडिया सरोकारों की वैचारिक त्रैमासिक पत्रिका।
3. **अतुल्यभारतम्** - विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक संस्कृत पत्रिका।
4. **पाकिस्तान मीडिया स्केन**- सार्क देशों का मीडिया और भारत परियोजना के अंतर्गत मासिक प्रकाशन। पाकिस्तान मीडिया में भारत की छवि एवं समाचारों को अवगत कराने वाला यह शोध प्रकाशन अध्येताओं के साथ जनसंचार और सुधी नागरिकों के लिए रूचिकर है।

विश्वविद्यालय का नवीन परिसर निर्माण

विश्वविद्यालय का अपना नवीन परिसर भोपाल के पास बिसनखेड़ी ग्राम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित 50 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन है।

दीक्षांत समारोह

विश्वविद्यालय द्वारा 16 मई 2018 को तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन विधानसभा भवन सभागार में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उप राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय श्री वैंकैया नायडू रहे। समारोह में शोधार्थियों को 27 पीएच. डी., 39 एम. फिल एवं 202 स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्रदान की गईं।

प्रोडक्शन डे

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की कार्य आधारित आवश्यक व्यवहारिक क्षमता, कौशल, दक्षता एवं कुशलता बढ़ाने के लिये प्रत्येक विभाग में प्रत्येक शनिवार को प्रोडक्शन डे आयोजित करने की पहल की गई है।

विशिष्ठ गोष्ठियाँ, परिसंवाद एवं व्याख्यान

विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सत्र में पाठ्यक्रम में व्यवहारिक पक्ष की पूर्ति के उद्देश्य से देश-प्रदेश के वरिष्ठ विद्वानों को व्याख्यान के लिये आमंत्रित किया गया।

मीडिया प्रबंधन विभाग

इस विभाग में 14-15 दिसम्बर 2018 को 'नये भारत के लिए प्रभावी रणनीति, संभावनाएँ और चुनौतियाँ' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की गयी।

नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग

आलोच्य अवधि में कलर मैनेजमेंट एस्थेटिक्स इन ट्रेडीशनल आर्ट एवं क्राफ्ट, प्रिन्टेड डायरी मेकिंग, विशिष्ट पैकेजिंग, 2डी एनीमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन विषय पर विशेष व्याख्यान हुए।

सेन्सीटाइजेशन ऑफ इंफार्मेशन एण्ड साइबर सिक्योरिटी पर दो दिवसीय सेमीनार और नोएडा में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर ''माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक एवं पत्रकारीय अवदान'' पर राष्ट्रीय सेमीनार किया गया।

विद्यार्थियों की उपलब्धि

''चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2018'' में लघु फिल्म 'भारत' की स्क्रीनिंग हुई। विद्यार्थियों द्वारा समाचार-पत्र प्रकाशन में योगदान दिया गया।

''मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'' भोपाल के सातवें विज्ञान मेले में 3डी प्रिन्टिंग मॉडल को मेरिट अवॉर्ड प्राप्त हुआ।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ, ओरछा में 'सुट्टा' की स्क्रीनिंग हुई। पुणे की ऑनलाइन गैलरी के लिये 'आराध्या भाग-दो' लघु फिल्म का चयन हुआ।

चंडीगढ़ में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के नवें राष्ट्रीय विज्ञापन फिल्म उत्सव में '3डी प्रिंटिंग टेक्नालॉजी' डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिये चयनित हुई।

गोवा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2018 में विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं कन्टेन्ट पर शोध कार्य किया। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 'तूर्यनाद 2018 हिन्दी महोत्सव' में वाद-विवाद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शंखनाद 2018 में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में भी विश्वविद्यालय को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। साधु वासवानी महाविद्यालय भोपाल में अंतरमहाविद्यालयीन वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की युवा संसद प्रतियोगिता में जनसंचार विभाग को द्वितीय एवं विशेष दक्षता पुरस्कार प्राप्त हुआ। देहरादून में 40वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कान्फ्रेन्स में सर्वश्रेष्ठ जनसंचार संस्थान वर्ग में विश्वविद्यालय सम्मानित हुआ।

बजट–एक दृष्टि

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

मांग संख्या – 32 शीर्ष (222) सूचना तथा प्रचार (आयोजनेत्तर)

(31 जनवरी 2018 की स्थिति में)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	(2304) निर्देशन और प्रशासन	20292.85	18765.49	18188.28	16450.73
2	(7248) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार	6000.00	5999.99	6000.00	5955.43
3	(5489) पत्रकारिता पुरस्कार प्रशिक्षण	98.00	88.64	98.00	2.68
4	(8688) म.प्र. सूचना केंद्र, नई दिल्ली	179.73	99.77	149.35	90.56
5	(2822) चलचित्र इकाई की स्थापना	725.00	692.83	725.00	400.67
6	(0994) क्षेत्र प्रचार	600.00	597.71	1500.00	1031.81
7	(4065) विशेष अवसरों पर प्रचार	6602.04	6592.62	8018.00	5420.59
8	(0223) प्रकाशन	421.60	420.61	472.50	237.71
9	(1294) वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को श्रद्धानिधि	120.00	98.10	120.00	77.84
10	(7437) पत्रकारों को लेपटाप प्रदाय	45.00	9.20	18.00	3.60
11	(0684) कार्यालय भवन निर्माण	100.00	70.00	500.00	70.00
12	(5620) समन्वित प्रचार–प्रसार	540.00	539.33	540.00	100.57
13	(8808) सूचना प्राद्यौगिकी संबंधी कार्य	–	–	0.01	–
14	(0102)अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	239.60	237.36	245.00	–
15	(0103) अनुसूचित जाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	264.27	263.82	271.47	–
	महायोग (मांग संख्या–32)	**36228.09**	**34475.47**	**36845.61**	**29842.19**

सामान्य प्रशासनिक विषय

आलोच्य अवधि में सहायक संचालक के 17 सीधी भर्ती के रिक्त पदों का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग, इंदौर को भेजा गया। विभाग के तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पद की पूर्ति का प्रस्ताव पी.ई.बी. को भेजे जाने की कार्रवाई प्रचलन में है।

पी.ई.बी. की प्रतीक्षा सूची से 03 उम्मीदवारों को संवर्ग-तीन में नियुक्ति दी जाकर रिक्त पदों पर पदस्थ किया गया। विभाग के 02 दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित है। राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की पदक्रम सूची- 2018 भी प्रकाशित की जा चुकी है।

विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान पेड- न्यूज संबंधी मामले, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सभी समाचार-पत्र, पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों की मॉनीटरिंग के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को 24 घण्टे सतत् तैनात किया गया।

कर्मचारी-कल्याण

कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान-वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति/उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ दिये जाने के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। पात्रतानुसार समयमान-वेतनमान दिये जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक 27 जुलाई, 2018 को की गई। कर्मचारी संघ की समस्याओं/कठिनाइयों, मांगों का यथोचित निराकरण संचालनालय स्तर पर किया गया। शासन स्तर पर निराकृत होने वाली मांगों के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं।

सोशल मीडिया/विभागीय प्रशिक्षण

पहली बार विभागीय अधिकारियों को सोशल मीडिया में प्रशिक्षित कर पारंगत किया गया। इससे शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर भी बेहतर तरीके से हुआ। सभी संभाग एवं जिला अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन 2018 की गतिविधियों का सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार और मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.) का प्रशिक्षण दिलवाया गया। स्वीप प्लान सहित निर्वाचन की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सोशल मीडिया पर प्रचार हुआ।

विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का कुशलता एवं दक्षता से निर्वहन करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को समय-समय पर गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के उपयोग के संबंध में वर्कशॉप, प्रशिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत ऑनलाईन सुविधा से संबंधित कार्यशाला, अचीविंग एक्सीलेंस थ्रू मल्टीपल इंटेलीजेंस पर तीन दिवसीय कार्यशाला, संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, Consultative Workshop on gender responsive planning and budgeting, वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट निर्माण संबंधी विषय का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों द्वारा दिलाया गया।

महिलाकर्मियों की समस्याओं का निराकरण

महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में मुख्यालय पर राजपत्रित महिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग में महिलाओं की पद-स्थापना सर्वाधिक मुख्यालय में है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से लंच रूम और प्रसाधन की व्यवस्था है। अधीनस्थ कार्यालयों में भी महिला कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। राज्य महिला आयोग के प्रचार-प्रसार कार्यों को संपादित करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को नामांकित किया गया है।

महिलाओं के चित्रण के बारे में मीडिया की आचरण संहिता

विभाग द्वारा इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् को पत्र लिखा गया है। परिषद् ने सूचित किया है कि परिषद मीडिया में महिलाओं के नकारात्मक चित्रण पर चिंतित है और इसे रोकने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है।

विभागीय प्रकाशन

जनसंपर्क विभाग द्वारा मासिक ''मध्यप्रदेश संदेश'' नियमित प्रकाशित किया जा रहा है। विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा साप्ताहिक ''रोज़गार और निर्माण'' का भी नियमित प्रकाशन हो रहा है।

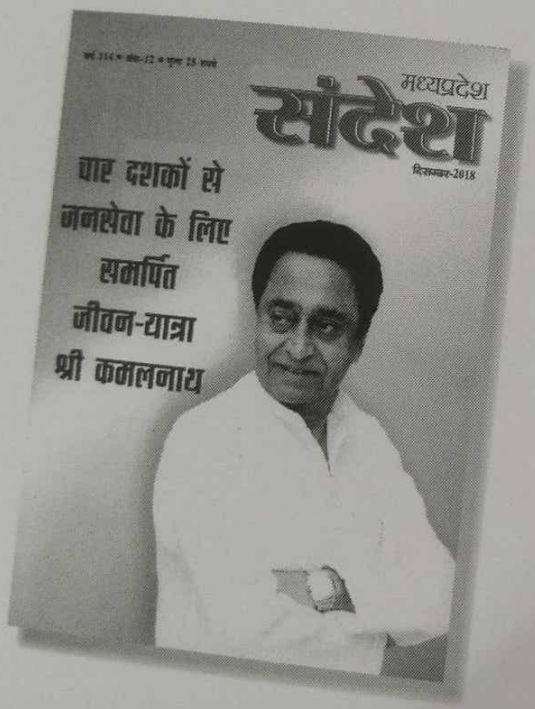

उपसंहार

जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कार्य शासन की जन-कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनता के हित में सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, आकाशवाणी, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, क्षेत्र प्रचार के पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों के साथ ही सोशल-डिजिटल मीडिया के जरिये जन-सामान्य तक पहुँचाना है। इस बार विधानसभा निर्वाचन 2018 में प्रदेश के सभी जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया गया।

सूचनाओं के विस्तार के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिला स्तर के समाचारों की उपलब्धता की दृष्टि से विभागीय वेबसाइट www.mpinfo.org., समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की क्लीपिंग के लिये www. mpnewsarch.org. , जिलों की खबरों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmpinfo.org सतत् कार्यशील है। इन साईट को मौजूदा परिवेश में नवीनतम स्वरूप देकर मोबाइल उपयोगी के साथ यूजर्स फ्रेंडली भी बनाया गया।

www.mpinfo.org

www.mpnewsarch.org

www.dprmpinfo.org

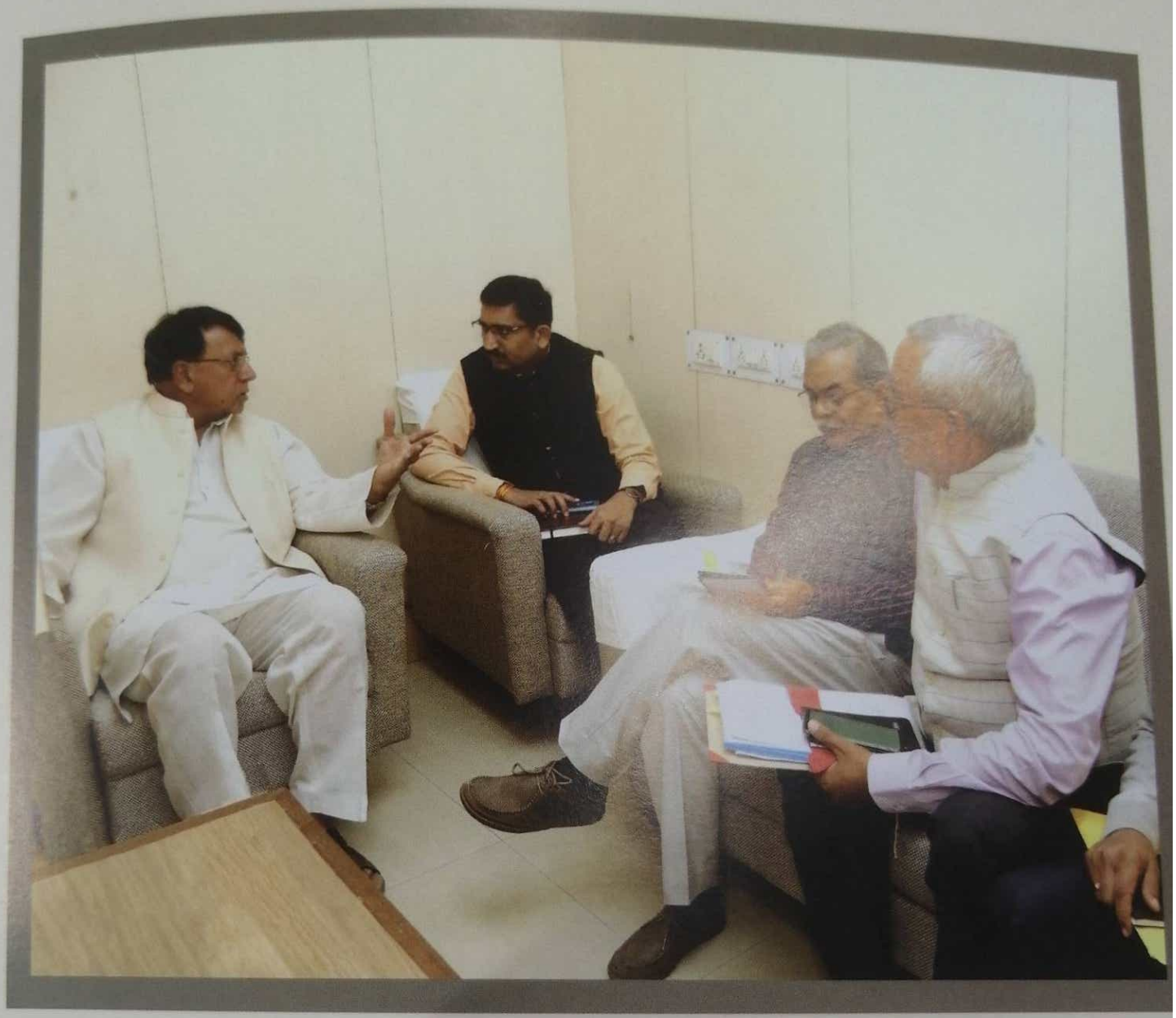

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंत्रालय में आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि और विभाग के अपर संचालकों से चर्चा की।

पहले ही दिन करके दिखाया

फसल कर्ज माफी का सबसे बड़ा वचन निभाया

देश में फसल ऋण माफी की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी योजना

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

- 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू
- 22 फरवरी से ऋण खातों में भुगतान शुरू

किसानों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ

प्रदेश के 55 लाख किसान होंगे लाभान्वित

पात्र किसानों के लगभग रु. 50 हजार करोड़ फसल ऋण माफी का अनुमान

योजना में
31 मार्च 2018 तक के
ऋण माफ होंगे और
12 दिसम्बर, 2018 तक
ऋण चुकाने वाले किसान
भी पात्र होंगे

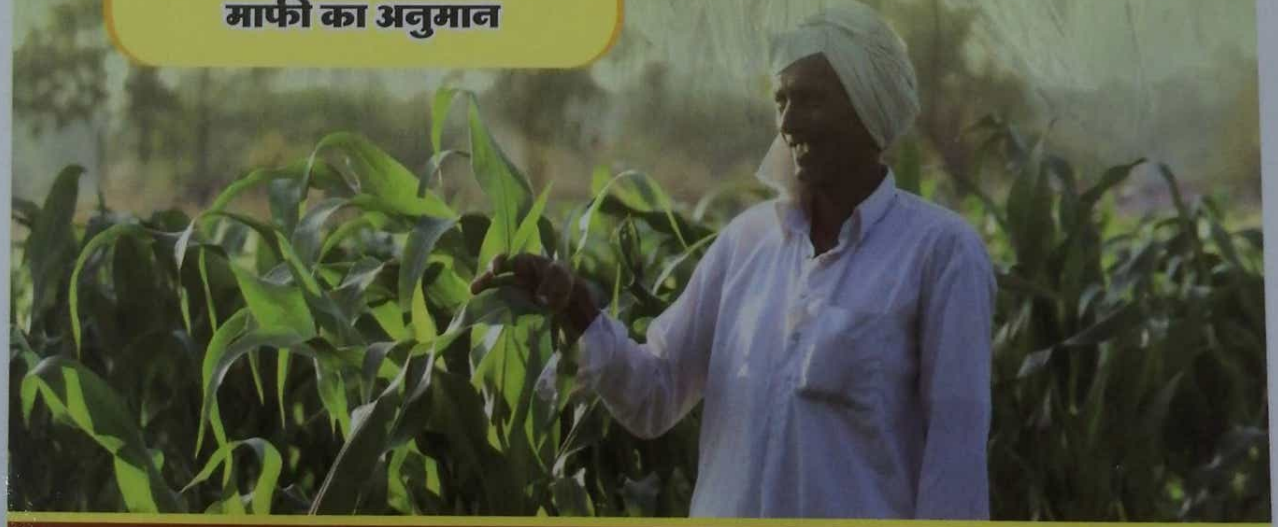

बदलाव के लिए संकल्पित, मध्यप्रदेश सरकार